

DAILY CURRENT AFFAIRS

IN HINDI

SPECIAL FOR UPSC & GPSC EXAMINATION

DATE : 31-12-25



यूपीएससी सीएसई के लिए द हिंदू महत्वपूर्ण समाचार लेख और संपादकीय

बुधवार, 31 दिसंबर, 2025

संस्करण : अंतर्राष्ट्रीय विषय-सूची

पेज 01 पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन III : भारतीय अर्थव्यवस्था	भारत अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है: केंद्र
पेज 06 पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन II : अंतर्राष्ट्रीय संबंध / प्रारंभिक परीक्षा	दक्षेस नेता खालिदा जिया का भारत के पड़ोस के साथ लगातार संपर्क था
पेज 08 पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन- III : भारतीय अर्थव्यवस्था / प्रारंभिक परीक्षा	अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली विपरीत परिस्थितियां जल्द दूर नहीं हो रही हैं
पेज 08 पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन-II: सामाजिक न्याय / प्रारंभिक परीक्षा	एक स्वास्थ्य मुद्दे के रूप में फांक देखभाल को प्राथमिकता देना
पेज 11 पाठ्यक्रम : सामान्य अध्ययन-II : भारतीय राजव्यवस्था / प्रारंभिक परीक्षा	'सजा के निलंबन' पर कानून
पेज 08 : संपादकीय विश्लेषण पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन- II : अंतर्राष्ट्रीय संबंध	द्विध्रुवीय विशेषताओं के साथ एक बहुध्रुवीय दुनिया

पृष्ठ 04 : सामान्य अध्ययन III : भारतीय अर्थव्यवस्था

एक सरकारी बयान के अनुसार, भारत आधिकारिक तौर पर जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जिसकी जीडीपी 4.18 ट्रिलियन डॉलर है। निरंतर उच्च विकास, मजबूत घरेलू मांग और अनुकूल व्यापक आर्थिक संकेतकों ने भारत को संभावित रूप से जर्मनी से आगे निकलने और लगभग 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए एक पथ पर रखा है। यह विकास भारत की सुधार के बाद की आर्थिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और वैश्विक आर्थिक शासन के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ है।

India is now the fourth largest economy: Centre

With GDP valued at \$4.18 trillion, India has surpassed Japan and is poised to displace Germany from the third rank in the next few years with a projected GDP of \$7.3 trillion by 2030, it says

Press Trust of India
NEW DELHI

India has surpassed Japan to become the world's fourth largest economy with a size of \$4.18 trillion and is poised to overtake Germany to become the third largest by 2030, the government said on Tuesday.

With continuing good growth numbers, India is also the world's fastest-growing major economy, it said.

India's real GDP grew 8.2% in the second quarter of 2025-26, up from 7.8% in the first quarter and 7.4% in the fourth quarter of the last fiscal.

"With GDP valued at \$4.18 trillion, India has surpassed Japan to become the world's fourth largest economy and is poised to displace Germany from the third rank in the next 2.5 to 3 years with a projected GDP of \$7.3 trillion by 2030," said the government in a statement providing a snapshot of reforms in 2025.

The U.S. is the world's



Domestic drivers, led by robust private consumption, played a big role in supporting this expansion, the government has said. AFP

largest economy, and China occupies the second spot.

The growth momentum further surprised on the upside, with GDP expanding to a six-quarter high in Q2 of 2025-26, reflecting India's resilience amid persistent global trade uncertainties, it said.

Domestic drivers, led by robust private consumption, played a central role in supporting this expansion.

The release said international agencies have echoed this optimism and

cited projections made by various entities. The World Bank has projected a 6.5% growth in 2026, and Moody's expects India to remain the fastest-growing G20 economy with a growth of 6.4% in 2026 and 6.5% in 2027. The International Monetary Fund has raised its projections to 6.6% for 2025 and 6.2% for 2026, and the Organisation for Economic Cooperation and Development forecasts 6.7% growth in 2025 and 6.2% in 2026. Also, the S&P anticipates a growth of 6.5% in the current fiscal

and 6.7% in the next, the Asian Development Bank has lifted its 2025 forecast to 7.2%, and Fitch has raised its FY26 projection to 7.4% on stronger consumer demand.

"India is among the world's fastest-growing major economies and is well-positioned to sustain this momentum. With the ambition of attaining high middle-income status by 2047 - the centenary year of its independence, the country is building on strong foundations of economic growth, structural reforms, and social progress," the government said.

The release highlighted that inflation remains below the lower tolerance threshold, unemployment is declining, and export performance continues to improve. Furthermore, financial conditions have stayed benign, with strong credit flows to the commercial sector, while demand conditions remain firm, supported by a further strengthening of urban consumption.

समाचार की मुख्य बातें

- भारत ने 2025-26 की दूसरी तिमाही में 8.2% वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर्ज की, जो छह तिमाहियों में सबसे अधिक है।
- मजबूत निजी खपत और शहरी मांग में सुधार के नेतृत्व में विकास घरेलू स्तर पर संचालित हुआ है।
- वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं के बावजूद भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है।

- कई अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने भारत की विकास संभावनाओं में विश्वास व्यक्त किया है:
- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2025 में 6.6% की वृद्धि का अनुमान लगाया है।
- विश्व बैंक ने 2026 में 6.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया है।
- आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने मध्यम अवधि में 6% से ऊपर की वृद्धि की उम्मीद की है।
- मुद्रास्फीति कम सहनशीलता बैंड से नीचे है, बेरोजगारी घट रही है, और वाणिज्यिक क्षेत्र में ऋण प्रवाह मजबूत बना हुआ है।

भारत की आर्थिक वृद्धि को चलाने वाले कारक

मजबूत घरेलू मांग: निजी खपत प्राथमिक विकास इंजन के रूप में उभरी है, जो बढ़ती आय, शहरीकरण और बेहतर उपभोक्ता विश्वास से समर्थित है।

व्यापक आर्थिक स्थिरता: नियंत्रित मुद्रास्फीति, स्थिर वित्तीय स्थिति और स्वस्थ बैंकिंग क्षेत्र की बैलेंस शीट ने निवेश और विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाया है।

संरचनात्मक सुधार: करधान (GST), दिवाला समाधान (IBC), डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (UPI, DBT) और उत्पादन-लिंकड प्रोत्साहन (PLI) में सुधार ने दक्षता और औपचारिकता में वृद्धि की है।

जनसांख्यिकीय लाभांश और सेवाओं की ताकत: एक युवा कार्यबल और आईटी, डिजिटल सेवाओं और ज्ञान-आधारित क्षेत्रों में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता दीर्घकालिक विकास का समर्थन करना जारी रखती है।

भारत और विश्व के लिए महत्व

वैश्विक आर्थिक स्थिति: भारत का उदय G20, IMF और विश्व बैंक जैसे वैश्विक संस्थानों में अपनी आवाज़ को मजबूत करता है।

ग्लोबल ग्रोथ सेंटर में बदलाव: उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से उभरते बाजारों में आर्थिक गतिशीलता के संक्रमण को मजबूत करता है।

रणनीतिक और भू-राजनीतिक प्रभाव: आर्थिक ताकत वैश्विक व्यापार और कूटनीति में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और सौदेबाजी की शक्ति को रेखांकित करती है।

विकासात्मक अवसर: उच्च सकल घरेलू उत्पाद सामाजिक खर्च, बुनियादी ढांचे के निर्माण और गरीबी में कमी के लिए राजकोषीय स्थान प्रदान करता है।

चुनौतियाँ और चेतावनियाँ

प्रति व्यक्ति आय अंतर: उच्च सकल घरेलू उत्पाद के बावजूद, प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत कम बनी हुई है।

रोजगार की गुणवत्ता: रोजगार सृजन को विकास के साथ तालमेल बिठाना चाहिए, विशेष रूप से विनिर्माण और औपचारिक क्षेत्रों में।

बाहरी कमजोरियाँ: ऊर्जा आयात पर निर्भरता और वैश्विक वित्तीय अस्थिरता के संपर्क में आना चिंताएँ बनी हुई हैं।

क्षेत्रीय और सामाजिक असमानता: बढ़ती असमानताओं से बचने के लिए विकास समावेशी होना चाहिए।

निष्कर्ष

दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत का उभरना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जो इसके घरेलू विकास मॉडल के लचीलेपन और दीर्घकालिक सुधारों के संचयी प्रभाव को दर्शाता है। हालाँकि, इस व्यापक आर्थिक सफलता को समावेशी, रोजगार-गहन और सतत विकास में बदलना केंद्रीय चुनौती बनी हुई है। यदि भारत प्रभावी रूप से अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाता है, विनिर्माण को मजबूत करता है और मानव पूंजी को गहरा करता है, तो यह 2047 तक एक उच्च मध्यम-आय वाला देश बनने की अपनी महत्वाकांक्षा को साकार करने के लिए अच्छी स्थिति में होगा, जो आर्थिक पैमाने को सामाजिक प्रगति के साथ जोड़ेगा।

UPSC प्रारम्भिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत की वृद्धि को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस संकेतक का उपयोग करके मापा जाता है?

- (a) GDP (PPP शर्तें)
- (b) वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर
- (c) वर्तमान कीमतों पर नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद
- (d) सकल राष्ट्रीय आय

उत्तर: (c)

UPSC मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इस उपलब्धि के पीछे के घरेलू कारकों का विश्लेषण करें और उन चुनौतियों की जांच करें जिन्हें भारत को इस विकास पथ को बनाए रखने के लिए पार करना होगा। (150 शब्द)

पृष्ठ 05 : सामान्य अध्ययन II : अंतर्राष्ट्रीय संबंध

बांग्लादेश की पूर्व प्रधान मंत्री खालिदा जिया का जीवन और राजनीतिक कैरियर, भारत-बांग्लादेश संबंधों के विकास और दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कूटनीति के कामकाज को समझने के लिए एक मूल्यवान लेंस प्रदान करता है। 1970 के दशक के अंत से 2010 के दशक के मध्य तक, लगातार भारतीय नेताओं के साथ उनकी व्यस्तताओं ने शासन परिवर्तन, घरेलू उथल-पुथल और क्षेत्रीय संकटों के बावजूद द्विपक्षीय संबंधों में निरंतरता को प्रतिबिंबित किया। सार्क-केंद्रित क्षेत्रीय सहयोग और भारत की पड़ोसी कूटनीति के संदर्भ में उनकी भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

SAARC leader Khaleda Zia had a constant engagement with India's neighbourhood

From finding a mention as the wife of Bangladesh President in the diplomatic records of a 1979 banquet to hosting the Indian Prime Minister in SAARC summits, the Bangladeshi leader has a long history of interactions with the Indian leadership; her last noted interaction with Indian leadership was in 2015 when she met Modi in Dhaka

Kallol Bhattacharjee
NEW DELHI

A part from deposed Prime Minister Sheikh Hasina, Khaleda Zia was the only Prime Minister from Bangladesh whose political and institutional interactions with the Indian leadership stretched back to the 1970s and continued till the 21st century.

Begum Zia, as she was known to the people of Bangladesh, started her public life as the spouse of then President of Bangladesh General Ziaur Rahman, and she was a witness to the diplomacy between India and Bangladesh during a difficult period in the 1970s.

Ms. Zia first found mention in Indian diplomatic records when Prime Minister Morarji Desai acknowledged her presence during a banquet in Dhaka during his visit to Bangladesh on April 16, 1979.

It was a visit that took place during a rough patch in bilateral relations. Just three-and-a-half years ago, Sheikh Mujibur Rahman was assassinated in Dhaka along with most of his fa-

mily members and Indira Gandhi, a well-wisher of Mujib, was out of power after being overthrown in the 1977 election.

Earlier, President Nilam Sanjiva Reddy had held a banquet for President Rahman on December 19, 1977, when he visited Delhi (without Ms. Zia) and was welcomed at the New Delhi airport by Desai.

The Rahmans were met by Prime Minister Indira Gandhi when they became the first foreign guests that Indira met after being sworn into office for her last term in office in January 1980. The high-level visits between the two sides came at a sensitive period during 1977-1980 as Sheikh Hasina, one of the two surviving children of the slain Mujib, was based in India during this time. As relations improved between the two sides after President Rahman's meeting with Indira, Ms. Hasina returned to Bangladesh on May 17, 1981.

On May 30, 1981, President Rahman was assassinated in a failed military coup while he was on a visit to Chittagong. Hearing of the violent death, Indira



Rich history: Former Prime Minister of Bangladesh Khaleda Zia with Prime Minister Narendra Modi and former Prime Minister Manmohan Singh. ANI/FILEPHOTO

said, "The shocking assassination of President Ziaur Rahman shows the instability which many developing countries are facing. We in India are vigilant and shall take all necessary steps to safeguard our interests."

First woman PM

In the first six months of 1991, the subcontinent witnessed several shockers. On April 29, Bangladesh was hit by one of the most destructive cyclones in history of the region and then on May 21, as India was get-

ting ready for the election, former Prime Minister Rajiv Gandhi was assassinated. But prior to these developments, on March 20, Ms. Zia took charge as the first female Prime Minister of Bangladesh.

On March 7, 1991, the Ministry of External Affairs had said, "Any government in Bangladesh as much as any government in India, realises the importance of good relations between the two neighbours. We had welcomed the return of democracy, when the results of the elections were an-

nounced a few days ago, and expressed our hope and intention to work with Bangladesh, to strengthen our bilateral relations, based on our mutual national interests."

India, like Bangladesh, was witnessing a transition and the outreach therefore was aimed at ensuring a working relationship with Prime Minister Zia. In the last week of May 1992, Ms. Zia was hosted by Prime Minister P.V. Narasimha Rao. She made it clear that SAARC, a dream project of her late husband, was

She was a witness to diplomacy between India and Bangladesh during a difficult period in the 1970s

close to her heart.

Next year, during April 10-11, 1993, Rao visited Dhaka when Ms. Zia hosted the seventh SAARC summit and welcomed the King of Bhutan Jigme Singye Wangchuck; President of Maldives Maumoon Abdul Gayoom; Nepal Prime Minister Girija Prasad Koirala; Prime Minister Nawaz Sharif of Pakistan and the Sri Lankan President Ranasinghe Premadasa. What made this outreach significant was that India and Bangladesh tried to put relations back on track after the regional tension spiked because of the demolition of Babri Masjid by Hindu karsevaks in Ayodhya.

Despite the tension, ties were maintained during this time and next year when a cyclone hit Bangladesh, India reached out with relief.

In her second full-fledged term during 2001-2006, the Gujarat riots of

2002 cast a shadow on bilateral ties and that apart, India's concerns on terrorism and insurgency did not attract sufficient attention from Bangladesh.

Yet, before the onset of political uncertainty in the second half of 2006, Ms. Zia visited India and held talks with Prime Minister Manmohan Singh and signed a revised trade pact. Prior to that, she had hosted the 13th SAARC summit in November 2005. Her last visit to India took place during October 28-November 3, 2012, when she was the Leader of the Opposition in the Jatiya Sansad.

She met Prime Minister Manmohan Singh. She started that trip by meeting her counterpart, then Leader of the Opposition in the Lok Sabha, Sushma Swaraj.

Her last noted interaction with the Indian leadership was in June 2015 when she came to Hotel Sonargaon in Dhaka where Prime Minister Narendra Modi met several Bangladeshi leaders after the India-Bangladesh Land Boundary Agreement was sealed.

समाचार के प्रमुख आयाम

1. द्विपक्षीय संबंधों में ऐतिहासिक निरंतरता

खालिदा जिया की भारत के साथ बातचीत दक्षिण एशिया में शीत युद्ध के युग की अशांति के दौरान शुरू हुई, जब बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान की मृत्यु के बाद हत्या के बाद की अस्थिरता से गुजर रहा था। जनरल जियाउर रहमान के कार्यकाल के दौरान राजनयिक कार्यक्रमों में उनकी शुरुआती उपस्थिति इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे राज्य-से-राज्य संबंध अक्सर व्यक्तिगत सरकारों से परे होते हैं। विभिन्न बिंदुओं पर भारतीय नेतृत्व के साथ वैचारिक मतभेदों के बावजूद, राजनयिक चैनल काम कर रहे हैं।

2. लोकतांत्रिक परिवर्तन और भारत की पड़ोसी नीति

1991 में बांग्लादेश की पहली महिला प्रधान मंत्री के रूप में उनका पदभार ग्रहण करना दक्षिण एशिया में लोकतांत्रिक बदलाव के साथ मेल खाता था। भारत की त्वरित पहुंच ने अपनी पड़ोस नीति के एक मूल सिद्धांत को रेखांकित किया: राजनीतिक अभिविन्यास के बावजूद निर्वाचित सरकारों के साथ जुड़ाव, स्थिरता और सहयोग पर जोर देना।

3. क्षेत्रीय एंकर के रूप में सार्क

- खालिदा जिया ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को लगातार महत्व दिया, जो उनके दिवंगत पति के साथ निकटता से जुड़ी एक पहल है।
- 7वें सार्क शिखर सम्मेलन (1993) और 13वें सार्क शिखर सम्मेलन (2005) की मेजबानी ने द्विपक्षीय तनाव को प्रबंधित करने के लिए क्षेत्रीय बहुपक्षवाद का उपयोग करने के बांग्लादेश के प्रयास को प्रदर्शित किया।
- यहां तक कि तनाव की अवधि के दौरान भी - जैसे कि बाबरी मस्जिद विध्वंस या गुजरात दंगों के बाद - सार्क शिखर सम्मेलनों ने बातचीत के लिए राजनयिक स्थान प्रदान किया, जो क्षेत्रीय मंचों के संस्थागत मूल्य को दर्शाता है।

4. द्विपक्षीय उपभेदों का प्रबंधन

- उनके कार्यकाल में बार-बार घर्षण देखा गया:
- सीमा पार आतंकवाद और उग्रवाद,
- व्यापार असंतुलन, और
- भारत और बांग्लादेश में घरेलू राजनीतिक घटनाक्रम। फिर भी, बातचीत जारी रही, जिसकी परिणति व्यापार समझौतों और उच्च स्तरीय यात्राओं में हुई, जिसमें मनमोहन सिंह के साथ बैठकें और बाद में 2015 में नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत शामिल थी।

5. 2015 की बातचीत का प्रतीकवाद

भूमि सीमा समझौते के बाद मोदी के साथ उनकी बैठक लंबे समय से चले आ रहे विवाद को खत्म करने का प्रतीक है और इस बात को रेखांकित करती है कि कैसे विपक्षी नेता भी बांग्लादेश में विदेश नीति की आम सहमति में हितधारक हैं।

निष्कर्ष

खालिदा जिया का भारत के साथ लंबा जुड़ाव अंतरराष्ट्रीय संबंधों के एक मूलभूत सिद्धांत को दर्शाता है: द्विपक्षीय संबंधों को केवल व्यक्तिगत नेताओं की तुलना में भूगोल, संस्थानों और रणनीतिक हितों द्वारा अधिक आकार दिया जाता है। उनका करियर दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं और सीमाओं दोनों को प्रदर्शित करता है, विशेष रूप से सार्क के माध्यम से। भारत के लिए, यह कहानी राजनीतिक चक्रों में पड़ोसी देशों के साथ निरंतर जुड़ाव के महत्व को पुष्ट करती है, जो क्षेत्रीय स्थिरता और दीर्घकालिक रणनीतिक प्रभाव के लिए एक प्रमुख स्तंभ है।

UPSC मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: बांग्लादेश में लगातार राजनीतिक बदलावों के बावजूद भारत-बांग्लादेश संबंधों ने परिवर्तन की तुलना में अधिक निरंतरता दिखाई है। (150 शब्द)

पृष्ठ 08 : सामान्य अध्ययन III : भारतीय अर्थव्यवस्था / प्रारंभिक परीक्षा

भारत के औद्योगिक क्षेत्र ने नवंबर 2025 में तीव्र तेजी दर्ज की, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में 6.7% की वृद्धि दर्ज की गई, जो 25 महीनों में सबसे तेज है, जिसके नेतृत्व में विनिर्माण में 8% का विस्तार हुआ है। हालांकि यह डेटा बिंदु पहली नज़र में उत्साहजनक प्रतीत होता है, एक करीबी जांच से पता चलता है कि उछाल एक टिकाऊ बदलाव के बजाय अस्थायी और मौसमी कारकों को दर्शाता है। संपादकीय इस बात पर प्रकाश डालता है कि नवंबर के औद्योगिक आंकड़ों के आसपास आशावाद गलत क्यों हो सकता है और यह अंतर्निहित आर्थिक हेडविंड के बारे में क्या प्रकट करता है।

नवंबर की वृद्धि मजबूत क्यों दिखाई देती है

फेस्टिव-सीजन रीस्टॉकिंग इफेक्ट: अक्टूबर में फेस्टिव सेल्स के बाद, फर्मों ने इन्वेंट्री को फिर से भर दिया, जिससे मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में अल्पकालिक बढ़ावा मिला। इस तरह की रीस्टॉकिंग-आधारित वृद्धि चक्रीय है, मांग-संचालित नहीं है, और आमतौर पर जल्दी से फीकी पड़ जाती है।

जीएसटी से संबंधित मांग को बढ़ावा दें: सरकार ने त्योहारी सीजन के आसपास माल और सेवा कर (जीएसटी) दरों में कटौती का समय निर्धारित किया, जिससे अस्थायी रूप से खपत को बढ़ावा मिला। इससे खरीदारी में तेजी आई लेकिन भविष्य के महीनों से मांग उधार ली गई, जिससे प्रभाव क्षणभंगुर हो गया।

उपभोक्ता वस्तुओं का पलटाव

- कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 10.3% (12 महीने का उच्च) ग्रोथ हुआ।
- उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं में 7.3% (25 महीने का उच्चतम) वृद्धि हुई: हालांकि, ये आंकड़े अप्रैल-नवंबर के रुझान के विपरीत हैं, जहां उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं में 1% की गिरावट आई, जो कमजोर बड़े पैमाने पर खपत को दर्शाता है।

खनन क्षेत्र की रिकवरी: विस्तारित मानसून के कारण दो महीने के संकुचन के बाद 5.4% की खनन वृद्धि हुई। मौसम से संबंधित रिकवरी स्वाभाविक रूप से गैर-दोहराए जाने योग्य हैं और संरचनात्मक सुधार का संकेत नहीं देती हैं।

स्पाइक के नीचे संरचनात्मक कमजोरियां

कमजोर मध्यम अवधि IIP ट्रेंड: अप्रैल-नवंबर 2025 के दौरान IIP की वृद्धि औसतन केवल 3.3% थी, जो सभी पोस्ट-कोविड वर्षों में इस अवधि के लिए सबसे कम है, जो औद्योगिक गति की नाजुकता को रेखांकित करती है।

RBI का सतर्क आउटलुक: भारतीय रिज़र्व बैंक ने वास्तविक GDP वृद्धि में मंदी का अनुमान लगाया है:

- **Q3 FY26:** लगभग 7%
- **Q4 FY26:** लगभग 6.5%: यह इस विचार के साथ संरेखित होता है कि नवंबर का स्पाइक एक बाहरी है।

Too good to last

The headwinds facing the economy are not going away soon

India's relatively strong industrial performance in November 2025, especially driven by the manufacturing sector as it was, was more likely a flash in the pan than the start of a consistent trend. The Index of Industrial Production (IIP) grew 6.7% in November, the fastest growth rate in 25 months. Within this, the manufacturing sector grew 8%, which also was the fastest in 25 months. On the face of it, this would look remarkable and heartening, especially since October 2025 had seen growth slow to a 14-month low. However, this surge in growth was more likely due to seasonal and one-off factors. According to economists, the strongest push for growth came from sellers re-stocking their supplies following the festive season. The second factor is that the government timed the Goods and Services Tax (GST) rate reductions to coincide with the festive season. This temporary bump in demand would have further eroded stock levels, which then need to be replenished. In fact, the consumer durables and non-durables sectors saw growth in November rebounding to 10.3% and 7.3%, a 12-month and 25-month high, respectively. The third factor that seems to have worked in November is the bounce back of the mining sector following two months of contractions due to an unseasonably long monsoon. The mining sector saw growth come in at a reasonably strong 5.4% in November 2025. All of these are legitimate reasons for growth to pick up, but are not sustainable ones. The electricity and mining sectors will be bound by the vagaries of the weather. Overall consumer demand has been sluggish and industry players are talking of the GST-related boost already ebbing. And the festive season will not come back around until October-November 2026.

In fact, the IIP grew just 3.3% in the longer April-November period, the lowest for these eight months in any of the post-COVID-19 pandemic years. The consumer non-durables sector contracted 1% during this period, showing that the boost in November is not indicative. That the strong growth in November is more an anomaly than a sign of things to come should not come as a surprise. The Reserve Bank of India, earlier this month, predicted that growth in Q3 would slow to 7% from an average of 8% in the first two quarters. The fourth quarter is predicted to slow even further, to 6.5%. All of the previous headwinds still exist. The 50% tariffs by the U.S. are still in place, private investment remains sluggish, foreign capital is pulling out of the country, the weakening rupee is making imports more expensive for an import-dependent economy, real wages are not growing fast enough, and consumer demand remains tepid. Ironically, November's positive industrial data bring into focus the headwinds the economy is really facing.

लगातार बाहरी और घरेलू प्रतिकूल हवाएं

- उच्च अमेरिकी टैरिफ (50%) निर्यात को बाधित करना जारी रखता है।
- विदेशी पूंजी का बहिर्वाह वित्तीय बाजारों पर दबाव डाल रहा है।
- आयात पर निर्भर अर्थव्यवस्था में रुपये के अवमूल्यन से आयात लागत बढ़ जाती है।
- सुस्त निजी निवेश और कमजोर वास्तविक मजदूरी वृद्धि खपत की मांग को रोक रही है।

मांग-पक्ष की बाधाएं: व्यापक-आधारित आय वृद्धि और रोजगार विस्तार की अनुपस्थिति निरंतर औद्योगिक सुधार को सीमित करती है। बड़े पैमाने पर मांग में पुनरुद्धार के बिना, विनिर्माण विकास कमजोर बना हुआ है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निहितार्थ

- अल्पकालिक डेटा अस्थिरता को संरचनात्मक ताकत के लिए गलत नहीं माना जाना चाहिए।
- राजकोषीय या कर-आधारित मांग उत्तेजनाओं पर अत्यधिक निर्भरता स्टॉप-गो चक्र बनाने का जोखिम उठाती है।
- सतत औद्योगिक विकास के लिए निजी निवेश के पुनरुद्धार, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता और वास्तविक आय वृद्धि की आवश्यकता होती है।

निष्कर्ष

नवंबर 2025 आईआईपी नंबर, हालांकि सतह पर प्रभावशाली हैं, लेकिन टिकाऊ रिकवरी के बजाय सांख्यिकीय और मौसमी विपथन के रूप में सबसे अच्छी व्याख्या की जाती है। एक महीने की वृद्धि और कमजोर मध्यम अवधि के रुझानों के बीच अंतर को उजागर करके, डेटा गहरी जड़ें जमा चुके आर्थिक विपरीत परिस्थितियों की दृढ़ता को रेखांकित करता है। भारत के औद्योगिक विकास को टिकाऊ बनाने के लिए, नीतिगत ध्यान अल्पकालिक मांग को बढ़ावा देने से निवेश, उत्पादकता और रोजगार आधारित आय वृद्धि जैसे संरचनात्मक चालकों पर केंद्रित होना चाहिए।

UPSC प्रारम्भिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. वे बड़े पैमाने पर खपत की मांग का एक अच्छा संकेतक हैं।
3. इस क्षेत्र में लगातार संकुचन घरेलू क्रय शक्ति में तनाव को इंगित करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर : c)

UPSC मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: वर्तमान में भारत के औद्योगिक विकास को बाधित करने वाली प्रमुख घरेलू और बाहरी बाधाओं का मूल्यांकन करें। अल्पकालिक लाभ को सतत विकास पथ में बदलने के लिए नीतिगत उपाय सुझाना। **(150 शब्द)**

पृष्ठ 09 : सामान्य अध्ययन II : सामाजिक न्याय

कटे होंठ और तालू (सीएलपी) भारत में सबसे आम जन्मजात विसंगतियों में से एक का प्रतिनिधित्व करते हैं, फिर भी उन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे के रूप में कम पहचाना जाता है। विश्व स्तर पर सबसे अधिक फांक जन्म के लिए भारत में योगदान करने के बावजूद - सालाना लगभग 36,000 मामले - देश में व्यापक राष्ट्रीय महामारी विज्ञान डेटा और एक एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया का अभाव है। लेख में समस्या के पैमाने और भारत के वर्तमान एनजीओ-संचालित, फांक देखभाल के लिए खंडित दृष्टिकोण की सीमाओं दोनों पर प्रकाश डाला गया है।

Prioritising cleft care as a health issue

More than 7,50,000 cleft surgeries were performed in India in the last 25 years by the international NGO Smile Train. This amounts to 30,000 surgeries annually. It is the highest by any organisation in the private or public sector. But the figures don't shine in India where one in 700 children are born with lip and/or palate deformity every year and there is a backlog of 7,000 corrective surgeries annually.

Smile Train India is among the NGOs that support and partner with skilled surgeons to provide free cleft surgeries and related care. While its contribution has benefited 7.5 lakh children so far, others, including Mission Smile, Operation Smile, Transforming Cleft and Healing Smile Foundation, have collectively benefited another 15 lakh children in the last 20 years. Their efforts deserve appreciation. However, they still fall short in India, which, despite recording the highest number of cleft births globally, has no national epidemiological data on cleft lip/palate.

Cleft lip/palate is a facial birth defect that occurs when certain tissues and structures do not fuse during pregnancy due to genetic factor or maternal nutrition deficiencies. It leaves newborns with a gap in the upper lip and the roof of the mouth. Independent surveys estimate that 36,000 babies are born with cleft abnormalities in India every year. About 68% of them rely on government hospitals for initial diagnosis, yet there are 17.5 lakh children with unrepaired clefts.

The situation in India

The situation is complex: there is lack of documentation of birth anomalies, and parental counseling on care and treatment is woefully inadequate. Also, the high cost of surgery deters families from seeking help. A decade ago, the Lancet Surgery Commission estimated a burden of 18.7% untreated Orofacial Clefts (OFC) in India. A 2022 report of the



Soma Basu

Comprehensive cleft care for children in India is driven by the non-profit private model. The government has achieved little in creating awareness or making cleft surgeries accessible and affordable to all

Institute for Health Metrics and Evaluation, University of Washington's School of Medicine, stated that children with OFCs in India were 1.5 times more vulnerable to severe malnutrition compared to other children under five. It also says one-third of the cleft lip and palate-related malnutrition deaths can be prevented with timely surgical treatment and proper nutrition.

Free or subsidised surgery and follow-up treatment are provided by NGOs in collaboration with mostly city-based private hospitals because government hospitals lack specialised infrastructure and trained personnel. The fragmented cleft care offered by government hospitals are not aggregated in public databases, maybe because India is yet to nationally recognise craniofacial anomalies as a notifiable disease.

The World Health Organization has formally recognised craniofacial anomaly in the Global Burden of Disease initiative. This is what perhaps led the NITI Aayog to initiate conversations around birth defects. The National Birth Defect Awareness Month launched in August 2024 on the theme 'Breaking Barriers: inclusive support for children with birth defects including clefts' helped discuss prevention, early identification, and timely management of common congenital malformations.

Surgeons play a key role in minimising birth defects. While people think of cleft lip and/or palate as a cosmetic deformity, it impacts a child's ability to speak, swallow, hear, and breathe. If not surgically corrected, babies with a cleft lip have difficulty nursing and require special feeding techniques. Children with a cleft lip get bullied and struggle with school and with communication. Employment and marriage become challenging. All this leads to psychological trauma and affects confidence. Ignorance and superstitions strengthen the stigma surrounding the disfigurement, and treatment is

marked by a rural-urban divide.

Every health challenge requires collaboration. Smile Train India and others address the gaps in cleft services with a sustainable and scalable global health model. This empowers local doctors as equal partners by providing support in training and covering surgical costs. As per the 2011 Census, 68.8% of the population in rural areas need to be covered aggressively. Collaborating with the Rashtriya Bal Swasthya Karyakram and ASHA for clear communication on early screening of birth defects and deficiencies is a way forward. In the absence of hospital partners in interior areas, timely medical intervention, with incentives that cover travel cost, surgery and hospital stay, and post-operative support including speech therapy, is imperative.

The way forward

UNICEF estimates that about 2.5 crore children are born in India annually. The 2022 National Family Health Survey states that 1.35 crore children are born in government hospitals, where cleft care in detected cases can ideally start at birth and life-transforming surgery can be done after three months of birth. It is time for policymakers to recognise cleft deformity as a health issue and opt for better management at the grassroots level, where there is limited awareness and access. The government can devise a multi-level approach to address under served communities. NGOs are trying to expand the footprint but government hospitals, where almost 50% of India's children are born, need to upgrade.

Health experts say cleft missions help strengthen government healthcare systems by improving surgical infrastructure, increasing access to affordable care, training the local workforce, and breaking social taboos. The success of cleft surgeries is measured by improved functionality, which depends on the age at which the child is brought for treatment.

समस्या की भयावहता और प्रकृति

- घटना: भारत में 700 में से लगभग 1 बच्चा कटे होंठ और/या तालू के साथ पैदा होता है।
- बैकलॉग: लगभग 17.5 लाख बच्चे बिना मरम्मत के फांकों के साथ रहते हैं, जिनमें लगभग 7,000 सर्जरी का वार्षिक बैकलॉग होता है।
- स्वास्थ्य प्रभाव: सीएलपी केवल कॉस्मेटिक नहीं है। यह भोजन, भाषण, श्रवण, श्वास और पोषण को प्रभावित करता है, जिससे गंभीर कुपोषण और मृत्यु दर की संभावना बढ़ जाती है।
- इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन (2022) के एक अध्ययन में पाया गया कि ओरोफेशियल क्लिफ्ट वाले बच्चों में गंभीर कुपोषण होने की संभावना 1.5 गुना अधिक होती है, और समय पर सर्जरी और पोषण से संबंधित एक तिहाई मौतों को रोका जा सकता है।

वर्तमान प्रतिक्रिया: ताकत और अंतराल

1. गैर सरकारी संगठनों की भूमिका

- स्माइल ट्रेन और अन्य जैसे अंतरराष्ट्रीय और घरेलू गैर सरकारी संगठनों ने पिछले दो दशकों में सामूहिक रूप से 22 लाख से अधिक सर्जरी को सक्षम बनाया है। उनका मॉडल इस पर केंद्रित है:
- स्थानीय सर्जनों के साथ साझेदारी,
- सर्जिकल लागतों को कवर करना, और
- प्रशिक्षण और पोस्ट-ऑपरेटिव सहायता प्रदान करना।
- प्रभावशाली होते हुए भी, यह दृष्टिकोण राष्ट्रीय मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है और बड़े पैमाने पर शहरी, निजी अस्पतालों में केंद्रित है।

2. कमजोर सार्वजनिक स्वास्थ्य एकीकरण

- भारत में फांक विसंगतियों के राष्ट्रीय स्तर के दस्तावेजीकरण का अभाव है।
- क्रानियोफेशियल विसंगतियाँ अधिसूचित बीमारियाँ नहीं हैं, जिससे कम रिपोर्टिंग होती है।
- सरकारी अस्पतालों, जहां लगभग 50% संस्थागत जन्म होते हैं, अक्सर विशेष बुनियादी ढांचे और फांक देखभाल के लिए प्रशिक्षित कर्मियों की कमी होती है।

3. ग्रामीण-शहरी विभाजन और सामाजिक कलंक

- भारत की लगभग 69% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जहां जागरूकता, शीघ्र निदान और सर्जरी तक पहुंच सीमित है।
- अंधविश्वास, कलंक, और परामर्श की कमी उपचार में देरी करती है, कार्यात्मक और मनोवैज्ञानिक परिणामों को खराब करती है।

नीति और संस्थागत संदर्भ

- विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज फ्रेमवर्क के तहत क्रानियोफेशियल विसंगतियों को पहचानता है, जो उनकी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रासंगिकता को रेखांकित करता है।
- भारत में, नीति आयोग ने जन्म दोषों पर चर्चा शुरू की है, और राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह (2024) इस मुद्दे को मुख्यधारा में लाने की दिशा में एक कदम है।

- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) और फ्रंटलाइन वर्कर्स (आशा) जैसी मौजूदा योजनाएं प्रारंभिक जांच और रेफरल के लिए एक तैयार मंच प्रदान करती हैं, लेकिन समन्वय कमजोर रहता है।

आगे की राह: क्या करने की आवश्यकता है

सीएलपी को सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे के रूप में मान्यता दें

- क्रानियोफेशियल विसंगतियों को सूचित करें और उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य डेटाबेस में एकीकृत करें।
- योजना और संसाधन आवंटन के लिए विश्वसनीय महामारी विज्ञान डेटा उत्पन्न करें।

सरकारी स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना

- जिला और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को विशेष शल्य चिकित्सा और भाषण-चिकित्सा सेवाओं के साथ अपग्रेड करना।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से सर्जनों और संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों को प्रशिक्षित करना।

प्रारंभिक पहचान और देखभाल की निरंतरता

- सरकारी अस्पतालों में जन्म के समय स्क्रीनिंग शुरू करें, जहां सालाना 1.35 करोड़ जन्म होते हैं (एनएफएचएस-5)।
- पोषण सहायता और भाषण चिकित्सा सहित अनुवर्ती देखभाल सुनिश्चित करें।

ग्रामीण और कम सेवा वाले क्षेत्रों को लक्षित करें

- गरीब परिवारों के लिए यात्रा, सर्जरी और पोस्ट-ऑपरेटिव प्रोत्साहन प्रदान करें।
- कलंक से निपटने और जागरूकता में सुधार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का उपयोग करें।

निष्कर्ष

कटे होंठ और तालू भारत में विकलांगता और बाल मृत्यु दर के एक उपेक्षित लेकिन रोके जा सकने वाले कारण का उदाहरण हैं। जबकि गैर सरकारी संगठनों ने महत्वपूर्ण अंतराल को भर दिया है, धर्मार्थ हस्तक्षेपों पर निर्भरता एक प्रणालीगत, राज्य के नेतृत्व वाले सार्वजनिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण का विकल्प नहीं हो सकती है। एक स्वास्थ्य मुद्दे के रूप में फांक विकृति को पहचानना, सरकारी अस्पतालों को मजबूत करना, और मातृ और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों के भीतर फांक देखभाल को एम्बेड करना प्रारंभिक हस्तक्षेप सुनिश्चित करने, कलंक को कम करने और जीवन के परिणामों में सुधार करने के लिए आवश्यक है। सीएलपी को संबोधित करना प्रभावी रूप से समावेशी स्वास्थ्य देखभाल, बाल पोषण और मानव पूंजी विकास के भारत के व्यापक लक्ष्यों के साथ संरेखित करता है।

UPSC मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: गैर-सरकारी संगठनों ने भारत में फांक देखभाल में एक प्रमुख भूमिका निभाई है, लेकिन उनके प्रयास अपर्याप्त हैं। फांक देखभाल के एनजीओ के नेतृत्व वाले मॉडल की ताकत और सीमाओं पर चर्चा करें और जांच करें कि मजबूत राज्य की भागीदारी क्यों आवश्यक है। (250 शब्द)

पृष्ठ 10 : सामान्य अध्ययन II : भारतीय राजव्यवस्था / प्रारंभिक परीक्षा

उन्नाव बलात्कार मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सजा के निलंबन, गंभीर अपराधों में न्यायिक विवेक और शक्तिशाली निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किए गए अपराधों से निपटने में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की पर्याप्तता को नियंत्रित करने वाले कानून पर महत्वपूर्ण बहस को फिर से शुरू कर दिया है। यह मामला आपराधिक प्रक्रिया, बाल संरक्षण कानून और समानता और न्याय के संवैधानिक मूल्यों के चौराहे पर बैठा है।

Law on ‘suspension of sentence’

In life imprisonment cases like Kuldeep Singh Sengar's, what factors must appellate courts weigh before suspending a sentence? Does the Delhi High Court's view that an MLA is not a 'public servant' under the POCSO framework expose a gap that weakens protection against aggravated abuses by elected representatives?

LETTER & SPIRIT Kartikey Singh

In December 29, a three-judge bench of the Supreme Court, comprising C.J. Surya, Justice J.K. Maheshwari and Justice A.G. Masih, issued notice and stayed the Delhi High Court's judgment suspending the life sentence of a former four-time MLA, Kuldeep Singh Sengar and granting him bail pending appeal in the 2017 infamous Unnao rape case. The intervention came just six days after the High Court, on December 23, suspended Sengar's life sentence, which triggered intense public debate.

The case stems from allegations that in June 2017, the survivor, then a minor, was raped by the convict, the then-sitting MLA, at his residence. Amid allegations of police inaction and intimidation, the probe was transferred to the CBI in April 2018, and the trial shifted to Delhi pursuant to the SC's directions. On December 16, 2019, the trial court in Delhi convicted Sengar, and by a separate order on December 20, 2019, sentenced him to imprisonment for the remainder of his natural life.

Once a trial concludes, an accused is either acquitted or convicted. A conviction displaces the "presumption of innocence" and renders the sentence operative, requiring the convict to undergo the awarded punishment. However, the conviction may be set aside on appeal, and the convict may be released. In such cases, the court may suspend the sentence and direct the convict to remain in custody, keeping its enforcement in abeyance. Importantly, suspension of sentence, which is a discretionary judicial power, halts only the punishment and not the finding of guilt.

When do courts suspend a sentence? The law draws a clear distinction between "suspension of sentence" in cases involving short-term or fixed-term sentences, where it is the norm, and in serious offences, often punishable with life imprisonment, where it is an exception. In *Bhagwan Rama Shinde Gosi vs. State of Gujarat* (1959), the SC held that when a fixed-term sentence is under appeal, appellate courts must liberally exercise their discretion to suspend the sentence, barring exceptional circumstances. Conversely, in serious offences or those punishable with life imprisonment, such as Sengar's case, "suspension of sentence" under Section 389 CrPc is rare and must follow an objective assessment of factors including the nature and gravity of the offence, the manner of its commission, and the desirability of releasing the convict on bail, as reiterated by the top court in *Shivani Tyagi vs. State of Uttar Pradesh* (2024), an acid attack case.

In allowing Sengar's 'suspension of sentence' application, the High Court focused primarily on his conviction under Section 362 of the POCSO Act, which criminalises 'aggravated' penetrative sexual assault by a "public servant" on a child and attracts punishment under Section 6. Under the criminal law framework, offences committed by persons in positions of trust or authority, such as police or armed force personnel, public servants, and staff of institutions including hospitals, jails, or educational



Public voices: Women stage a protest demanding justice for the Unnao gangrape victim outside Delhi High Court in New Delhi, Aug.

establishments, are treated as 'aggravated' and subjected to enhanced punishment, reflecting legislative recognition of abuse of power and heightened victim vulnerability. Definition of public servant Importantly, the POCSO Act does not define the term "public servant." Under Section 2(2) of the POCSO Act, undefined expressions shall draw their meaning from the IPC (1860), CrPc (1973), the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, or the Information Technology Act, 2008. Among these, only the IPC defines "public servant" under Section 21, encompassing categories such as judges, military officers, and arbitrators, etc., but not elected legislators. Relying on this statutory scheme and the top court's ruling in *R.S. Nayak vs. A.R. Antulay* (1984), the HC held that an MLA does not qualify as a "public servant" under the IPC and, consequently, the POCSO Act. This is a departure from the trial court's approach, which had sustained Sengar's conviction under Section 5(c) by importing the broader definition of "public servant" from Section 2(1)(b) of the Prevention of Corruption Act (PCA), 1988, which includes any person holding an office to perform a public duty.

Consequently, the HC held, prima facie, that Sengar's case did not fall within the category of rape committed by a "public servant" under Section 5(c) of the POCSO Act or Section 376(2)(b) IPC. This finding formed the central basis for suspending his sentence and granting regular bail. The HC also noted that Sengar had undergone over seven years of imprisonment, and, relying on *Kashmira Singh vs. State of Punjab* (1977), observed that prolonged incarceration could cause injustice if the conviction or sentence were ultimately modified.

Addressing the survivor's apprehension of threat, rooted in a documented history of systemic intimidation, the custodial death of her father (for which Sengar stands convicted under Section 304(b) IPC), police callousness, and the 2019 truck-car accident that critically injured her and her lawyer and killed her two aunts, the HC noted that the SC had granted her CrPc protection in August 2019. Nevertheless, the HC held that "suspension of sentence" could not be denied solely on the apprehension that

police or paramilitary forces might fail in their protective duties, as such a premise would undermine their role.

In a case that laid bare a prolonged struggle for justice, structural barriers and deep institutional failures in confronting entrenched power, the suspension of a life sentence raises serious concerns.

First, while the HC is legally correct in holding that it could not expand the statutory definition of "public servant" by amending the legislation to import the broader meaning under the PCA, its interpretation could have been more purposive. The resulting anomaly is troubling: while a *paisani* (village accountant) or police constable qualifies as a "public servant" and attracts punishment under the POCSO Act, an elected MLA does not. This ambiguity in the POCSO framework was also flagged by the SC bench. By narrowing the scope of the POCSO Act, a special, victim-centric statute designed to protect children, the HC accorded insufficient weight to its object and intent. Offences under Section 5(c) are undoubtedly graver than corruption offences by MPs or MLAs: while corruption undermines governance, offences under the POCSO Act involve the direct abuse of children, causing severe physical and psychological trauma with lasting social consequences.

The apex court has repeatedly cautioned against interpretive legalism that weakens POCSO's protective core. In *Attorney General for India vs. Satish* (2021), it rejected the Bombay HC's untenable narrow interpretation that grouping a minor through clothing, without direct "skin-to-skin" contact, did not amount to "touch" or "physical contact" so as to attract the offence of "sexual assault" under Section 7 of the POCSO Act. Similarly, in *Independent Thought vs. Union of India* (2017), the SC harmoniously and purposively interpreted child-protection law by reading down Exception 2 to Section 375 IPC, which had exempted non-consensual sexual intercourse with one's wife aged between 15 and 18, from the offence of rape. Together, these rulings affirm that when child protection is at stake, statutory interpretation must advance, not dilute, the law's protective purpose.

Second, the HC's decision rests primarily on the prima facie inapplicability of Section 5(c) of the POCSO Act and the period of

incarceration already undergone. However, the SC has held that in cases involving life imprisonment, 'suspension of sentence' under Section 389 CrPc requires the appellate court to assess whether the convict has a fair chance of acquittal. Recently, in *Ohlwalia Yadav vs. State of Haryana* (2025), the apex court set aside a 'suspension of sentence', holding that in life imprisonment cases, suspension is warranted only where the convict demonstrates a palpable or gross error in the trial court's judgment sufficient to show that the appeal may succeed and result in acquittal. In Sengar's case, the HC ought to have examined whether the non-applicability of Section 5(c) would lead to his complete acquittal. Further, in *Shivani Tyagi vs. State of Uttar Pradesh* (2024), the SC clarified that long incarceration alone cannot justify 'suspension of sentence' in life imprisonment cases.

In the same vein, in *Jenna Lal vs. State of Rajasthan* (2025), involving a POCSO conviction carrying a 20-year sentence, the SC set aside an order suspending sentence, holding that once the trial court has found the victim to be a minor, such a finding cannot be lightly unsetled at the suspension stage.

Third, the HC should have accorded greater weight to the undisputed record of intimidation and violence, including the survivor's father's death, alleged witness tampering, and the exceptional security measures required during trial.

What is next? The HC's literal interpretation highlights a statutory framework that recognises authority only when formally mentioned, not when exercised through entrenched political power, as seen in the definition of "public servant." This limitation is legislatively inherited, not judicially created. While legality and justice often align, they do not always converge.

Beyond legal questions, the case also exposes how the criminal justice system operates for survivors of sexual violence. It lays bare the fact that, in reality, the fundamental right of equality before law and equal protection of laws under Article 14 of our Constitution is not truly treated as equal for every individual. Yet, these courageous survivors bear the cost not to vindicate the system, but to reveal its limits and expand justice for all. Kartikey Singh is a lawyer based in New Delhi. Views expressed are personal.

THE GIST

The law draws a distinction between 'suspension of sentence' in cases involving short-term or fixed-term sentences, where it is the norm, and in serious offences, where it is an exception.

'Suspension of sentence', which is a discretionary judicial power, halts only the punishment and not the finding of guilt.

The POCSO Act does not define the term 'public servant.' The Act says undefined expressions shall draw their meaning from the IPC, CrPc, the Juvenile Justice Act, 2015, or the IT Act, 2008.

कानूनी ढांचा: सजा का निलंबन

- सीआरपीसी, 1973 की धारा 389 (अब बीएनएसएस, 2023 की धारा 430) के तहत, अपीलीय अदालतें अपील के लंबित रहने के दौरान सजा के निष्पादन को निलंबित कर सकती हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विकसित प्रमुख सिद्धांतों में शामिल हैं:
- दोषसिद्धि के बाद की धारणा: एक बार दोषी ठहराए जाने के बाद, निर्दोषता की धारणा अब काम नहीं करती है; सजा का निलंबन एक अपवाद है, खासकर आजीवन कारावास के मामलों में।

- भगवान राम शिंदे गोसाई बनाम गुजरात राज्य के मामले में, न्यायालय ने माना कि निलंबन आम तौर पर अल्पकालिक सजा के लिए उदार है।
- इसके विपरीत, आजीवन कारावास सहित गंभीर अपराधों में, निलंबन के लिए अपराध की प्रकृति, गंभीरता और बरी होने की संभावना की सख्त जांच की आवश्यकता होती है, जैसा कि शिवानी त्यागी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में दोहराया गया है।
- हाल ही में न्यायशास्त्र, जैसे छोटेलाल यादव बनाम झारखंड राज्य, स्पष्ट करता है कि अकेले लंबे समय तक कैद रहना अपर्याप्त है; अपीलीय अदालत को यह आकलन करना चाहिए कि क्या बरी होने की वास्तविक संभावना का संकेत देने वाली कोई स्पष्ट त्रुटि है।

मुख्य विवाद: POCSO के तहत 'लोक सेवक'

- दिल्ली उच्च न्यायालय का निलंबन आदेश काफी हद तक उसके प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि एक विधायक पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 (सी) के उद्देश्य से "लोक सेवक" नहीं है, जो एक लोक सेवक द्वारा एक बच्चे पर गंभीर यौन हमले को अपराध बनाता है।
- POCSO "लोक सेवक" को परिभाषित नहीं करता है और आईपीसी जैसे कानूनों से परिभाषाएं उधार लेता है।
- आईपीसी की धारा 21 में निर्वाचित विधायकों को शामिल नहीं किया गया है, जबकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत व्यापक परिभाषा है।
- आरएस नायक बनाम ए आर अंतुले पर भरोसा करते हुए, उच्च न्यायालय ने पीसीए परिभाषा को आयात करने से इनकार कर दिया।
- यह शाब्दिक व्याख्या एक वैधानिक अंतर को उजागर करती है: निचले स्तर के अधिकारी POCSO के तहत "लोक सेवक" के रूप में अर्हता प्राप्त करते हैं, लेकिन अपार वास्तविक शक्ति रखने वाले निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं करते हैं। ऐसा परिणाम पीड़ित-केंद्रित, बाल-संरक्षण कानून के उद्देश्य और उद्देश्य के साथ असंगत प्रतीत होता है।

उद्देश्यपूर्ण व्याख्या और बाल संरक्षण

- सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार उद्देश्यपूर्ण व्याख्या पर जोर दिया है जहां बाल अधिकार शामिल हैं:
- इंडिपेंडेंट थॉट बनाम यूनिन ऑफ इंडिया में नाबालिगों के लिए मैरिटल रेप अपवाद को शामिल किया गया है।
- भारत के अटॉर्नी जनरल बनाम सतीश के मामले में, इसने पॉक्सो सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक संकीर्ण रीडिंग को खारिज कर दिया।
- इस न्यायशास्त्रीय पृष्ठभूमि के खिलाफ, उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण POCSO के सुरक्षात्मक कोर को कमजोर करने का जोखिम उठाता है, खासकर राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग से जुड़े मामलों में।

सेंगर मामले में व्यापक चिंताएं

डराने-धमकाने का इतिहास अपर्याप्त है: रिकॉर्ड में उत्तरजीवी के पिता की हिरासत में मौत, कथित गवाह को धमकी और असाधारण सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। ये कारक "रिहाई की वांछनीयता" के लिए प्रासंगिक हैं, जो धारा 389 के तहत एक महत्वपूर्ण परीक्षण है।

कानून के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14): वास्तविक शक्ति के बजाय औपचारिक वैधानिक परिभाषाओं के आधार पर विभेदक परिणाम वास्तविक समानता और उत्तरजीवियों के लिए न्याय तक पहुंच के बारे में चिंता पैदा करते हैं।

विधायी बनाम न्यायिक जिम्मेदारी: जबकि अदालतें क़ानूनों को फिर से नहीं लिख सकती हैं, यह मामला POCSO के तहत गंभीर श्रेणियों के भीतर निर्वाचित प्रतिनिधियों को स्पष्ट रूप से शामिल करने के लिए विधायी हस्तक्षेप की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

निष्कर्ष

उन्नाव मामला इस बात को रेखांकित करता है कि सजा का निलंबन एक प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय है, लेकिन आजीवन कारावास और पॉक्सो मामलों में इसका अभ्यास असाधारण और पीड़ित-संवेदनशील होना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय की "लोक सेवक" की व्याख्या एक विधायी अंधे स्थान को उजागर करती है जो बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों की जवाबदेही को कमजोर करती है। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप तत्काल संतुलन बहाल करता है, लेकिन टिकाऊ न्याय वैधानिक स्पष्टता, उद्देश्यपूर्ण व्याख्या और एक आपराधिक न्याय प्रणाली की मांग करता है जो सार्थक रूप से शक्ति विषमताओं का सामना करता है। तभी संविधान के तहत कानून के समक्ष बाल संरक्षण और समानता के वादे को साकार किया जा सकता है।

UPSC प्रारम्भिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: भारतीय आपराधिक कानून के तहत सजा के निलंबन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. सजा के निलंबन के परिणामस्वरूप दोषसिद्धि का निलंबन होता है।
2. आजीवन कारावास से जुड़े मामलों में, सजा का निलंबन अपवाद के बजाय नियम है।
3. आजीवन कारावास के मामलों में सजा के निलंबन के लिए अकेले लंबी कैद ही पर्याप्त आधार है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 3
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: d)

UPSC मुख्य - निबंध परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न : जहाँ कानून समाप्त हो जाता है, वहाँ न्याय की कोई संभावना नहीं रहती। (300 शब्द)

A multipolar world with bipolar characteristics

As 2025 draws to a close, a highlight is that the United States has undertaken its largest troop mobilisation in the Caribbean in decades. Its Navy has deployed its most advanced aircraft carrier, along with fighter jets, amphibious vessels, attack submarines and tens of thousands of troops, as it intensifies its pressure on Venezuela in an effort to force President Nicolás Maduro from power.

The Trump administration's National Security Strategy (NSS), released in early December 2025, identifies Latin America and the Caribbean as a strategic priority. Reviving the 19th century Monroe Doctrine, the document asserts that the U.S. must deny influence or control by outside powers (read China) in Latin America and ensure that the Western Hemisphere remains under American political, economic and military influence.

The push to reinforce American primacy in Latin America coincides with U.S. President Donald Trump's waning interest in Europe, another long-standing U.S. sphere of influence. Since the end of the Second World War, the U.S. has served as Europe's primary security guarantor. If Washington kept western Europe together through a tightly knit alliance during the Cold War, it expanded this security umbrella to eastern Europe after the disintegration of the Soviet Union, creating a large transatlantic bloc. Under Mr. Trump, however, the U.S. is no longer interested in shouldering the burden of European security – a position explicitly articulated in the NSS. Why is America, at a moment when Russia and China are seeking to overturn the U.S.-built and U.S.-led security and economic order, stepping back from Europe while moving to consolidate its influence in the Western Hemisphere?

It is difficult to discern a cohesive doctrine in Mr. Trump's foreign policy, marked by the President's impulses and unpredictability. Yet, even these impulses, this unpredictability and his ideological orientation rooted in Christian nationalism and America's might cannot ignore the structural shifts reshaping the international order. Mr. Trump is not the 'President of peace' that he claims to be – he has already bombed six countries, even if he has stopped short of a full-scale war.

At the same time, Mr. Trump, despite his rhetoric about American military and economic dominance, recognises that he no longer lives in a unipolar world. His reluctant aggression and strategic recalibration are reflections of the changes now taking shape in the global balance of power.

Three great powers

When the Soviet Union disintegrated in 1991, a new order emerged with the U.S. at its centre. There was no other great power positioned to challenge American primacy. The unipolar moment, however, has since passed. While future historians may better identify the precise point of



Stanly Johny

rupture, one such moment was Russia's annexation of Crimea in 2014. The ensuing conflict in eastern Ukraine, the tepid western response, and Russia's ability to endure despite sanctions reinforced the limits of the 'rules-based order'.

The end of unipolarity, however, does not mean the end of American dominance. The U.S. remains, and will remain, for the foreseeable future, the world's pre-eminent military and economic power. What has changed is that Washington is no longer the sole great power shaping geopolitical outcomes. China and Russia now occupy that space as well, deepening what Realist thinkers describe as the inherently anarchic nature of the international system.

During the Cold War, the Soviet Union was America's principal rival, and in the 1970s, Washington reached out to China to exploit fissures within the communist bloc. Today, the U.S. identifies China as its principal and systemic challenger. This, in turn, leaves open the possibility of a reset in ties with Russia – an idea embraced by Mr. Trump's MAGA (Make America Great Again) ideologues, who frame Russia as part of a shared 'Christian civilisation'.

The reigning power versus the rising power

The U.S. faces a unique challenge in China. The Soviet economy, in its prime in the early 1970s, reached about 57% of the U.S. GDP, before it began slowing down. China's economy, now the world's second largest, already amounts to about 66% of the U.S. economy. China continues to grow at a faster pace, steadily narrowing the gap.

As China's economic power expands, it is being converted into military capability (it has already built the world's largest Navy, by number of ships). Like other great powers, Beijing is seeking to establish regional hegemony and global dominance. So, a prolonged contest between the U.S., the reigning power, and China, the rising power, appears unavoidable. The situation is comparable to 19th century Europe, when a rising imperial Germany threatened to upstage Britain during Pax Britannica, unsettling the 'Concert of Europe'.

Russia is the weakest link among the three powers. It is a relatively smaller economy with a shrinking sphere of influence. But Russia's nuclear arsenal, expansive geography, abundant energy and mineral resources and its demonstrated willingness to use force to achieve its strategic objectives keep it in the great power constellation. From Moscow's perspective, the country drifted into the wilderness in the 1990s before announcing its return in 2008 with the war in Georgia. Since then, it has sought to rewrite the post-Soviet security architecture in Europe. As the West, having expanded the North Atlantic Treaty Organization into the Russian sphere of influence, responded to Vladimir Putin's war in Ukraine with sweeping sanctions on Russia and military support for Kyiv, Moscow moved ever closer to China. Russia and China

have found common ground in opposing the western 'rules-based order' – Russia thinks that the order denies it its rightful place in the world and seeks to revise it accordingly, while China, by contrast, as Rush Doshi argues in *The Long Game*, wants to replace it with a China-centric order.

Fluid multipolarity

All three great powers today understand that the world is no longer organised around a single centre of authority. In that sense, the world is already multipolar. But unlike the post-Second World War and post-Cold War transitions, the structures of the new order have yet to fully emerge. During the Cold War, the world was divided into two ideological blocs and two largely separate economic systems. Today, China lacks the kind of satellite state networks that characterised the 20th century superpowers, while the U.S. is reassessing the sustainability of its alliance frameworks, including its commitment to Europe.

Russia, with its own great power ambitions, is wary of being seen as a Chinese ally irrespective of its close strategic partnership with Beijing. This opens a window for a Washington-Moscow reset. But the war in Ukraine remains a stumbling block. Russia may not want to challenge America's global leadership, but it certainly wants to re-establish its primacy in its sphere of influence.

Thus, there are three great powers with divergent interests that are pulling the global order in different directions, rendering the emerging multipolarity fluid rather than as a structured system akin to the post-Second World War order. This also means that middle powers, including superpower allies such as Japan and Germany, and autonomous actors such as India and Brazil, would continue to hedge their bets.

Mr. Trump wants Europe to shoulder greater responsibility for its own security, reset relations with Russia and reassert American primacy in its immediate neighbourhood even as Washington prepares for a prolonged great power competition with China. The idea is to return to the classic offshore balancing. Even if Mr. Trump fails in executing it, future American Presidents may not be able to ignore the shifts that he has initiated. Russia, for its part, seeks to carve out a sphere of influence. China aims to preserve its close strategic partnership with Russia to keep the Eurasian landmass within its orbit, while establishing regional hegemony in East and Southeast Asia – moves that would cement its status as a long-term superpower, much as the U.S. did by asserting its hegemony in the Western Hemisphere in the 19th century, and across the Atlantic in the 20th century. In this fluid landscape, Russia has emerged as the new 'swing great power' between the two superpowers, paradoxically lending the emerging multipolar order a distinctly bipolar character.

stanly.johny@thehindu.co.in

सामान्य अध्ययन पेपर I: अंतर्राष्ट्रीय संबंध

UPSC मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न : एकध्रुवीय क्षण बीत चुका है, लेकिन अमेरिकी प्रभुत्व नहीं बीत चुका है। चीन के उदय और रूस के पुनरुत्थान से चिह्नित उभरती वैश्विक व्यवस्था के संदर्भ में इस कथन की आलोचनात्मक जांच करें। (150 शब्द)

संदर्भ :

जैसे-जैसे वैश्विक शक्ति समीकरण बदलते जा रहे हैं, 2025 में अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली तेजी से मजबूत द्विध्रुवीय प्रवृत्तियों के साथ एक बहुध्रुवीय संरचना को दर्शाती है। पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिकी शक्ति का नए सिरे से दावा, एक प्रणालीगत चुनौती देने वाले के रूप में चीन का उदय, और एक विघटनकारी लेकिन महत्वपूर्ण अभिनेता के रूप में रूस की भूमिका शीत युद्ध के बाद की एकध्रुवीय व्यवस्था के क्षरण को रेखांकित करती है। लेख इन विकासों को डोनाल्ड ट्रम्प के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति अभिविन्यास के भीतर रखता है, इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे वैश्विक शक्ति में संरचनात्मक परिवर्तन, केवल नेतृत्व विकल्पों के बजाय, विश्व राजनीति को नया आकार दे रहे हैं।

एकध्रुवीयता से द्रव बहुध्रुवीयता तक

एकध्रुवीय क्षण का अंत: 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद, अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा। हालांकि, 2014 में रूस के क्रीमिया पर कब्जे और चीन के निरंतर आर्थिक उदय जैसी घटनाओं ने अमेरिका के नेतृत्व वाले "नियम-आधारित आदेश" की सीमाओं को उजागर किया। दुनिया आज किसी एक केंद्र के इर्द-गिर्द नहीं घूमती है।

अमेरिकी प्रधानता की दृढ़ता: एकध्रुवीयता के क्षरण के बावजूद, संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे शक्तिशाली सैन्य और आर्थिक अभिनेता बना हुआ है। कैरेबियन में इसकी हालिया सेना की लामबंदी और मोनरो सिद्धांत का पुनरुद्धार क्षेत्रीय आधिपत्य को मजबूत करने के प्रयास का संकेत देता है, भले ही वाशिंगटन कहीं और, विशेष रूप से यूरोप में प्रतिबद्धताओं को फिर से व्यवस्थित करता है।

तीन महान शक्तियां, असमान लेकिन प्रभावशाली

- संयुक्त राज्य अमेरिका: शासन करने वाली शक्ति, अपतटीय संतुलन की ओर बढ़ते हुए वैश्विक नेतृत्व को बनाए रखने की मांग कर रही है।
- चीन: उभरती हुई शक्ति, आर्थिक ताकत को सैन्य क्षमता में परिवर्तित करना और पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया में क्षेत्रीय आधिपत्य का लक्ष्य रखना।
- रूस: परमाणु क्षमताओं, ऊर्जा संसाधनों और बल प्रयोग करने की इच्छा के कारण आर्थिक रूप से सबसे कमजोर लेकिन रणनीतिक रूप से परिणामी।

बहुध्रुवीयता के भीतर द्विध्रुवी विशेषताएँ

केंद्रीय धुरी के रूप में अमेरिका-चीन: शीत युद्ध के विपरीत, जहां विचारधारा ने द्विध्रुवीय प्रतिद्वंद्विता को संरचित किया, आज की प्रतियोगिता मुख्य रूप से भू-आर्थिक और भू-राजनीतिक है। चीन की अर्थव्यवस्था, जो पहले से ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था के आकार का लगभग दो-तिहाई है, और इसकी बढ़ती नौसैनिक शक्ति लंबे समय तक प्रतिद्वंद्विता को अपरिहार्य बनाती है।

रूस एक 'स्विंग ग्रेट पावर' के रूप में: रूस एक अद्वितीय स्थान रखता है। पश्चिमी व्यवस्था के खिलाफ रणनीतिक रूप से चीन के साथ गठबंधन करते हुए, यह एक जूनियर पार्टनर बनने से सावधान रहता है। यह वाशिंगटन और मॉस्को के बीच सामरिक पैतरेबाज़ी के लिए जगह बनाता है, जिससे सिस्टम को बहुध्रुवीय सेटिंग के भीतर द्विध्रुवी गतिशीलता मिलती है।

फिक्स्ड ब्लॉक्स की अनुपस्थिति: शीत युद्ध के गठबंधनों के विपरीत, आज का आदेश तरल है। चीन के पास नाटो की तुलना में एक औपचारिक गठबंधन नेटवर्क का अभाव है, और अमेरिका विशेष रूप से यूरोप में लंबे समय से चली आ रही सुरक्षा प्रतिबद्धताओं का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है। यह तरलता एक स्थिर बहुध्रुवीय क्रम के क्रिस्टलीकरण को रोकती है।

मध्य शक्तियों के लिए निहितार्थ

- भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी जैसे देश बैंडबाजे के बजाय हेजिंग कर रहे हैं, कठोर गठबंधनों के बजाय मुद्दा-आधारित संरेखण का लाभ उठा रहे हैं।
- रणनीतिक स्वायत्तता और लचीली कूटनीति एक ऐसी दुनिया में महत्व प्राप्त करती है जहां शक्ति केंद्र कई हैं लेकिन प्रतिस्पर्धा केंद्रित है।

निष्कर्ष

समकालीन अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली न तो वास्तव में बहुध्रुवीय है और न ही पूरी तरह से द्विध्रुवीय है। यह एक तरल, संक्रमणकालीन क्रम है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच प्रतिद्वंद्विता द्वारा आकार दिया गया है, जिसमें रूस एक महत्वपूर्ण स्विंग पावर के रूप में कार्य करता है। जबकि अमेरिकी प्रभुत्व समाप्त नहीं हुआ है, यह तेजी से लड़ा जा रहा है। इस उभरते परिदृश्य में, कठोर गठबंधन संरचनाएं रणनीतिक हेजिंग का मार्ग प्रशस्त करती हैं, और वैश्विक स्थिरता निश्चित आदेशों पर कम और अनुकूली कूटनीति पर अधिक निर्भर करती है। भारत जैसे देशों के लिए, यह क्षण एक जटिल, प्रतिस्पर्धी और अनिश्चित दुनिया में नेविगेट करने के लिए जोखिम और अवसर दोनों प्रदान करता है।